



सोना, चांदी और मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है

पर सेजरस्थान में
कोठी की रेट हमेशा
ऊपर ही जाएगी।



KEDIA
सेजरस्थान
KOTHI & WALK-UP APARTMENT



अजमेर रोड़, जयपुर

बड़ी-बड़ी कोठी, बड़े-बड़े फ्लैट



कोठी

₹ 4700/ Sq Ft
से शुरू

वॉक-अप अपार्टमेंट

₹ 4000/ Sq Ft
से शुरू

FIXED PRICE & RENTAL

PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	FIXED PRICE	PROPOSED RENTAL
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	65 LACS	22,000
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	75 LACS	25,000
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	80 LACS	28,000
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.05 CRORE	30,000
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.21 CRORE	40,000
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.51 CRORE	50,000

पजेशन शुरू
अब हर महीने रेट और बढ़ेगी



विचार बिन्दु

बच्चों को पालना, उन्हें अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना भी सेवाकार्य है, क्योंकि यह उनका जीवन सुखी बनाता है। –स्वामी रामसुखदास

शिक्षा का बदलता स्वरूप: राजस्थान में चुनौतियां और संरक्षण के सरकारी उपाय

शिक्षा मानव सभ्यता का मूल आधार है। यह व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्यों से सुसज्जित कर समाज की प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। आजादी के बाद से भारत में शिक्षा का स्वरूप निरंतर विकसित हो रहा है, लेकिन डिजिटल युग ने इसे अभूतपूर्व गति प्रदान की है। कोविड-19 महामारी ने पारंपरिक कक्षा-कक्ष शिक्षा को ऑनलाइन मॉड में धकेल दिया, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एआई आधारित लर्निंग ऐप्स और वर्चुअल क्लासरूम मुख्यधारा बन गए। राजस्थान जैसे विविधतापूर्ण राज्य में यह परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप तेजी से घटित हो रहा है। राज्य सरकार ने डिजिटल डिवाइड, गुणवत्ता ह्रास और सांस्कृतिक क्षय जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु बहुआयामी संरक्षण उपाय अपनाए हैं।

शिक्षा का परंपरागत स्वरूप गुरुकुल परंपरा पर आधारित था, जहाँ गुरु-शिष्य संबंध के माध्यम से समग्र विकास होता था। औद्योगिक क्रांति और वैश्वीकरण ने इसे औपचारिक स्कूलों तक सीमित कर दिया। अब 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी ने इसे क्रांतिकारी रूप प्रदान किया है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और हाई-स्पीड इंटरनेट ने शिक्षा को सीमाहीन बना दिया। एनईपी 2020 ने इसे पुष्ट किया, जिसमें 5 3 3 4 की नई संरचना अपनाई गई-फाउंडेशन (3-8 वर्ष), प्रिपेटरी (8-11), मिडिल (11-14) तथा सेकेंडरी (14-18)। बहुभाषिकता, कौशल विकास और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर जोर दिया गया। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं, एनपीटीईएल, ई-पाठशाला जैसे पोर्टल्स लाखों छात्रों को जोड़ रहे हैं। एआई आधारित प्लेटफॉर्म जैसे बायजूज, अनएकेडमी छात्र की गति अनुसार पाठ्यक्रम ढालते हैं। वर्चुअल रियलिटी (वीआर) से छात्र ताजमहल के अंदर भ्रमण कर वास्तुकला सीख सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, 2025 में राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में वीआर के माध्यम से उदयपुर के झील का डिजिटल दौरा कराया गया, जिससे छात्रों की रुचि दोगुनी हो गई। ये नवाचार शिक्षा को रोचक और सुलभ बना रहे हैं।

राजस्थान में यह परिवर्तन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढल रहा है। राज्य में 1.07 लाख से अधिक स्कूल हैं, जहाँ 7.75 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। 2023-24 से विश्वविद्यालय स्तर पर एनईपी लागू हो चुकी है। स्कूली स्तर पर चरणबद्ध क्रियान्वयन जारी है-2025-26 से कक्षा 1-5 में नया सिलेबस शुरू हुआ, जिसमें उदयपुर द्वारा तैयार भारतीय संस्कृति, इतिहास और व्यावहारिक ज्ञान शामिल है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जुलाई 2025 से प्राथमिक स्तर पर बड़े बदलाव की घोषणा की। एनसीईआरटी, एनसीएफ 2023 और राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप वीर योद्धाओं, राजस्थान भूगोल, लोक संस्कृति को पाठ्यक्रम में स्थान मिला। डिजिटल इंडिया के तहत भारत नेट परियोजना ने ग्रामीण पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा है। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसए) ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को साक्षर बनाया, जिसमें राजस्थान का बड़ा हिस्सा शामिल है। 2026 तक राज्य में 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच गया, जिससे 50 लाख छात्र लाभान्वित हुए।

शिक्षा का बदलता स्वरूप अवसर है, लेकिन असंतुलित हो तो विनाशकारी भी साबित हो सकता है। राजस्थान सरकार के उपाय एनईपी चरणबद्ध क्रियान्वयन, सिलेबस संशोधन, सांस्कृतिक एकीकरण प्रेरक हैं। समग्र शिक्षा, डिजिटल पहलें मील का पत्थर साबित हो रही हैं। समाज, शिक्षक, अभिभावक, नीति-निर्माता मिलकर प्रयास करें। राजस्थानी धरोहर सहेजें, आधुनिकता अपनाएँ। युवा सशक्त हों, राज्य प्रगति करे। विश्व गुरु भारत का स्वन साकार हो।

15 प्रतिशत गिरा। तृतीय, सांस्कृतिक क्षया पश्चिमी एडटेक ऐप्स से राजस्थानी लोकगीत, कठपुतली, भोपाओं की परंपरा प्रभावित हो रही है। गुरु-शिष्य संबंध कमजोर पड़ गया। चतुर्थ, निजीकरण। कोचिंग संस्थान और एडटेक कंपनियाँ बाजारीकरण कर रही हैं, जिससे गरीब वंचित रह रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, जयपुर के कोटा जैसे शहरों में एडटेक फीस 20 प्रतिशत बढ़ी, जबकि ग्रामीण आय समान रही।

राजस्थान सरकार ने शिक्षा संरक्षण हेतु सक्रिय कदम उठाए हैं। समटा शिक्षा अभियान (2021-26) के तहत 2.15 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें राज्य को पर्याप्त हिस्सा मिला। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड स्थापित हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संभागीय कमेटीयों गठित कीं, जो 186 स्कूलों का अपग्रेड सुनिश्चित कर रही हैं। 2026 तक 500 और स्कूल स्मार्ट बनेंगे। राजस्थानी भाषा प्रोत्साहन योजना से क्षेत्रीय भाषा, लोककथाएँ, लोकगीत पाठ्यक्रम में शामिल हैं। कला एवं हस्तशिल्प शिक्षा योजना स्कूलों में लोककलाएँ-कठपुतली, मांडणा, भोपा नृत्य सिखा रही है। एनईपी में भारतीय ज्ञान प्रणाली वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेद को स्थान दिया गया। डीआईटी और डिजिटल आईसीटी शिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। नवोदय विद्यालयों का विस्तार मेधावी ग्रामीण छात्रों हेतु हो रहा है। पोर्टल से 25 प्रतिशत आरक्षण, छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को गति मिली। मिड-डे मील नामांकन बढ़ा रहा है। कोविड में डीआईएसएचए ने टीवी, रेडियो से 20 करोड़ छात्रों तक पहुँचा। एनएएस कमजोर क्षेत्र चिह्नित कर रहा है। जयपुर में पाठ्यक्रम समीक्षा समिति विश्वविद्यालय शिक्षाविदों संग कार्यरत है। बीकानेर के 15 स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। ये उपाय भाषाई विविधता मारवाड़ी, मेवाड़ी को सम्मान देते हैं।

सांस्कृतिक संरक्षण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजस्थान सरकार ने स्थानीय परंपराओं को एनईपी से जोड़ा। स्कूलों में भजन संध्या, कवि सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। हस्तशिल्प से छात्र स्वरोजगार सीख रहे हैं। महिला साक्षरता हेतु विशेष अभियान चल रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा लागू है। डिजिटल सुरक्षा हेतु साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा से प्री-प्राइमरी तक एकीकरण हुआ। उदाहरणस्वरूप, जोधपुर के एक स्कूल में भोपा कलाकारों ने छात्रों को लोककथाएँ सिखाईं, जिससे सांस्कृतिक जुड़ाव 40 प्रतिशत बढ़ा। फिर भी कमियाँ बरकरार हैं। शिक्षा बजट जीडीपी का 6 प्रतिशत होना चाहिए, वर्तमान लगभग 4 प्रतिशत है। भ्रष्टाचार, क्रियान्वयन देरी बाधा बने हुए हैं। नामांकन ह्रास चिंताजनक है 2025 में प्राथमिक स्तर पर 5 प्रतिशत गिरावट दर्ज। रेगिस्तानी क्षेत्रों में इंटरनेट समस्या बनी हुई। निजीकरण नियंत्रण अपर्याप्त है। भविष्य हेतु एआई का नैतिक उपयोग आवश्यक सांस्कृतिक सामग्री युक्त ऐप्स विकसित करें। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाएँ। शिक्षक भर्ती तेज करें। 2026 के राज्य बजट में 10,000 नई भर्तियाँ प्रस्तावित हैं।

शिक्षा का बदलता स्वरूप अवसर है, लेकिन असंतुलित हो तो विनाशकारी भी साबित हो सकता है। राजस्थान सरकार के उपाय एनईपी चरणबद्ध क्रियान्वयन, सिलेबस संशोधन, सांस्कृतिक एकीकरण प्रेरक हैं। समग्र शिक्षा, डिजिटल पहलें मील का पत्थर साबित हो रही हैं। समाज, शिक्षक, अभिभावक, नीति-निर्माता मिलकर प्रयास करें। राजस्थानी धरोहर सहेजें, आधुनिकता अपनाएँ। युवा सशक्त हों, राज्य प्रगति करे। विश्व गुरु भारत का स्वन साकार हो। सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े आधुनिक नागरिक गढ़ों संरक्षण हो प्रगति का आधार है।

–अतिथि संपादक,

अविनाश जोशी,

वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

राशिफल

शनिवार 7 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, चित्रा नक्षत्र रात्रि 2:28 तक, शूल योग रात्रि 11:40 तक, गर करण दिन 2:07 तक, चन्द्रमा आज दिन 1:32 से तुला राशि में संचार करेगा।
गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 2:28 से सूर्योदय तक है। रविवोग रात्रि 2:28 से आरम्भ होगा। महापात योग रात्रि 9:37 से रात्रि 2:22 तक है। भद्रा रात्रि 2:55 से आरम्भ होगी।
श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:35 से 9:57 तक, चर 12:41 से 2:03 तक, लाभ-अमृत 2:03 से 4:47 तक।
राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 7:13, सूर्यास्त 6:09

मेघ
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। दिन के मध्याह्न पश्चात परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला
व्यावसायिक यात्रा संभव है। नौकरिपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक बातों सफल रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मिथुन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक बातों सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
परिवार शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यक्तिगत विवासां से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक बातों सफल रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। दिन के मध्याह्न पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

मीन
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

दो वर्ष बनाम पांच वर्ष : राजस्थान में सुशासन, गति और विश्वास का नया अध्याय

यदि दावे के स्तर पर नहीं, बल्कि आंकड़ों की कसौटी पर परखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में शासन की शैली और प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव आया है



मदन राठौड़

राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक इतिहास में यह पहला अवसर है, जब कोई सरकार अपने कार्यकाल के मात्र दो वर्षों में न केवल अपने कामकाज का आंकड़ों सहित रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे, बल्कि उसे पूर्ववर्ती सरकार के पूरे पाँच वर्षों से तुलनात्मक रूप से बेहतर सिद्ध करने का दावा भी आत्मविश्वास के साथ रखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान प्रस्तुत किया गया दो वर्षों की उपलब्धियों का दस्तावेज़ इसी आत्मविश्वास का प्रतिफल है।

यह दस्तावेज़ केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय अनुशासन और विकास की स्पष्ट दिशा का संकेत देता है। मुख्यमंत्री का यह कथन कि पूर्ववर्ती कांग्रेस

सरकार के पाँच वर्षों से अधिक कार्य हमारी सरकार ने दो वर्षों में किए हैं, यदि दावे के स्तर पर नहीं, बल्कि आंकड़ों की कसौटी पर परखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में शासन की शैली और प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव आया है।

पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय कुप्रबंधन का गहरा प्रभाव पड़ा। 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ रुपये का कर्ज, खाली खजाना और अथूरी योजनाओं की विरासत नई सरकार को मिली। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार ने केवल दो वर्षों में राजस्व घाटे को करीब 8 हजार करोड़ रुपये तक कम कर दिया। वर्ष 2023-24 में 38 हजार 954 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे को 2025-26 के बजट अनुमानों में 31 हजार 9 करोड़ रुपये तक लाना वित्तीय अनुशासन का स्पष्ट संकेत है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक क्षेत्र में नवाचार और प्रशासनिक सुधारों की विशेष सराहना इस बात की पुष्टि करती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को केवल स्थिरता ही नहीं, बल्कि गति और दिशा भी मिली है।

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राज्य में भजनलाल शर्मा की सरकार के कारण डबल इंजन की अवधारणा धरातल पर साकार होती दिखी है। जहां पूर्ववर्ती सरकार को चार वर्षों में 15,803 करोड़ रुपये की पूंजीगत

निवेश सहायता मिली, वहीं वर्तमान सरकार मात्र दो वर्षों में 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सहायता केंद्र से प्राप्त कर चुकी है। वर्ष 2024-25 में 30 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय अब तक का सर्वाधिक है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष राजस्थान को 90 हजार 445 करोड़ रुपये प्राप्त होना भी इस सहयोग का प्रतिफल है।

रामजल सेतु परियोजना के अंतर्गत नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध में जल संग्रहण प्रारंभ होना, 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का धरातल पर उतरना और यमुना जल समझौते की डीपीआर का अंतिम चरण राजस्थान के जल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में निर्णायक कदम है।

जहाँ पिछली सरकार ने पाँच वर्षों में 52,182 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा दी, वहीं वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में ही 99,562 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि नीति और क्रियान्वयन की गति का भी है। कृषि क्षेत्र में किसान सम्मान निधि को दो वर्षों में डेढ़ गुना करना और 10,508 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करना सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। 48,325 करोड़ रुपये के व्याज मुक्त फसली ऋण, 73 लाख से अधिक फसल बीमा पॉलिसियां और 6,415 करोड़ रुपये का क्लेम वितरण

जैसे कदम किसानों के आर्थिक संबल को मजबूत करते हैं।

22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली, 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन और 48,591 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी मिलकर ठामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करता है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश पेपरलोक जैसे मामलों पर सरकार की सख्ती है। 140 एफआईआर और 428 से अधिक अपराधियों को जेल भेजना केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि भरोसे की बहाली है। अब तक 1 लाख से अधिक नियुक्तियाँ, 1 लाख 55 हजार से अधिक भर्तियाँ प्रक्रियाधीन और निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार अवसर यह दर्शाता है कि सरकार रोजगार को घोषणाओं से निकालकर धरातल पर ला रही है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अपराधों में 14.13 प्रतिशत की कमी, एससी-एसटी अत्याचारों में 28 प्रतिशत और महिला अपराधों में 10 प्रतिशत की गिरावट, ये आंकड़े कानून-व्यवस्था में सुधार की पुष्टि करते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पूर्ववर्ती सरकार को तुलना में 35 प्रतिशत अधिक भुगतान, एनएफएसए में 73 लाख से अधिक नए लाभार्थी, 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर से 1 करोड़ परिवारों को राहत जैसे सभी कदम सामाजिक न्याय के विस्तार को दर्शाते हैं।

स्वास्थ्य, ऊर्जा और औद्योगिक भविष्य

–पुस्तक समीक्षा–

‘‘सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि’’

लेखक : वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान



वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान।

दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, जो समय के साथ बदलता नहीं, बल्कि समय को दिशा देता है। अटल बिहारी वाजपेयी इसी सनातन चेतना के वाहक थे। चाहे संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में दिया गया उनका ऐतिहासिक भाषण हो या विपक्ष में रहते हुए भी लोकतांत्रिक

मर्यादाओं का पालन-हर प्रसंग में लेखक सनातन मूल्यों की झलक दिखाते हैं। पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अटल जी के प्रमुख राजनीतिक निर्णयों को सांस्कृतिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया गया है। पोखरण परमाणु परीक्षण को केवल

सामरिक निर्णय न मानकर लेखक उसे

राष्ट्र की आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जोड़ते हैं। इसी प्रकार, सड़क, संचार और आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं को ‘राष्ट्र निर्माण के यश’ के रूप में देखा गया है। लेखक यह तर्क देते हैं कि अटल जी का विकास महत्त्व केवल भौतिक उन्नति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सांस्कृतिक और मानवीय विकास को भी समान महत्व देता था।

शैली की दृष्टि से पुस्तक सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली है। भाषा न तो अत्यधिक दार्शनिक है और न ही शुष्क राजनीतिका। यही कारण है कि यह पुस्तक सामान्य पाठकों, विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी के लिए भी सहज रूप से पठनीय बन जाती है। लेखक का अनुभव और वैचारिक स्पष्टता हर अध्याय में महसूस होती है। कई स्थानों पर अटल जी के विचार, कथन और घटनाएँ पाठक को भावनात्मक रूप से भी जोड़ती हैं।

पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी को एक आदर्श लोकतांत्रिक नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक बताते हैं कि सत्ता में रहते हुए भी अटल जी ने कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। विरोधियों के प्रति सम्मान, संवाद की संस्कृति और संसदीय मर्यादाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज के राजनीतिक परिदृश्य में और अधिक प्रासंगिक

प्रतीत होती है।

पुस्तक अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रश्न भी उठाती है कि क्या आज की राजनीति अटल जी के मूल्यों से कुछ सीख लेने की तैयार है? हालाँकि, पुस्तक का वैचारिक झुकाव स्पष्ट है और यह अटल जी के व्यक्तित्व का अत्यंत सकारात्मक चित्र प्रस्तुत करती है। आलोचनात्मक विश्लेषण की अपेक्षा करने वाले पाठकों को यह पक्ष थोड़ा सीमित लग सकता है। फिर भी, पुस्तक का उद्देश्य आलोचना नहीं, बल्कि प्रेरणा देना है-और इस कसौटी पर यह पूरी तरह सफल होती है।

निष्कर्ष रूप में ‘सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि’ एक प्रेरक, विचारोत्तेजक और समयानुकूल कृति है। यह पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी को समझने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और राष्ट्रचिंतन को भी गहराई से समझने का अवसर देती है। जो पाठक अटल जी के विचारों, सनातन संस्कृति के मूल्यों और भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को जानना चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक अवश्य पठनीय है। यह केवल अटल जी को स्मरण करने की पुस्तक नहीं, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करने का आमंत्रण है।

(पुस्तक समीक्षक-गोपेन्द्र नाथ भट्ट स्वतन्त्र लेखक और सलाहकार विधानसभाध्यक्ष, राजस्थान है।)

जिला कलैक्टर ने ग्राम उत्थान शिविर का किया निरीक्षण

कलैक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान कर लाभान्वित कराया जाए

अलवर, (निसं)। जिला कलैक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने उपखण्ड क्षेत्र राजगढ़ के गिरदारवार सर्फिल ढिगावडा में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किसानों को वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान कीं।

जिला कलैक्टर ने शिविर में कृषि, पशुपालन, कॉर्पोरेटिव, राजस्व, ऊर्जा, चिकित्सा विभाग सहित 12

विभागों की लगाई गई स्टालों का निरीक्षण कर शिविर प्रभारी को निर्देश दिये कि आमजन के मूलभूत कार्यों को शिविर में ही सम्प्रादित कराये। उन्होंने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी आवेदक को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की तारबंदी, डिग्री, पावरलाइन, फार्म पॉण्ड, फव्वारा एवं ड्रिप, प्लास्टिक

मल्च, सौर पंप संयंत्र की स्वीकृतियां, बैलों से खेती करने पर 30 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि, फसल बीमा एवं एमएसपी की जानकारी, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, सॉलर हेल्थ काई वितरण, सोलर पंप एवं पॉलीहाउस के आवेदन तैयार करने सहित बीज एवं मिनी फिट वितरण का सत्यापन, पीएमएफएमई के आवेदन तैयार करना, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के

आवेदनों का निस्तारण, मुख्यमंत्री किसान निधि का डीबीटी, किसान क्रेडिट काई आवेदन, नवीन गोदाय निर्माण, डीसीएस द्वारा सहकारी बैंक में खाते, स्वयं सहायता समूहों के ऋण, 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना, सहकारिता सदस्यता आवेदन अभियान, सहकारी ऋण योजना की जानकारी एवं कस्टम हार्वरिंग सेंटर, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अंतर्गत पंजीकरण, पशुओं की

प्राथमिक चिकित्सा एवं कुमिनाशक औषधि पिलाना, क्लासिकल स्वाइन फीवर रोग प्रतिरोधक टीकाकरण, कुत्रिम गर्भाधान, फर्टिलिटी किट का वितरण, पशु आहार एवं खनिज मिश्रण वितरण तथा गौशाला विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान कर लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि ग्राम उत्थान शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लें।



पंडित अनिल शर्मा

कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 2:28 से सूर्योदय तक है। रविवोग रात्रि 2:28 से आरम्भ होगा। महापात योग रात्रि 9:37 से रात्रि 2:22 तक है। भद्रा रात्रि 2:55 से आरम्भ होगी।
श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:35 से 9:57 तक, चर 12:41 से 2:03 तक, लाभ-अमृत 2:03 से 4:47 तक।
राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 7:13, सूर्यास्त 6:09

तुला
व्यावसायिक यात्रा संभव है। नौकरिपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक बातों सफल रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक बातों सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। दिन के मध्याह्न पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

मीन
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।



संसद में कांग्रेस की मुख्य रणनीतिकार के रूप में उभरीं प्रियंका

पहली बार संसद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन बेहद असरदार नज़र आया

- सूत्रों ने बताया कि, कहाँ बैनर लगाने हैं, कौनसे नारे बोलने हैं, सब प्रियंका गांधी ने तय किया। यहाँ तक कि अब तक चुप रहने वाले सांसदों को बोलने का अवसर दिया गया।
- इसमें सबसे प्रभावी रूप से उभरे नागालैण्ड के एक सांसद, जिन्हें कोई नहीं जानता था, प्रियंका ने उन्हें किरेन रिजीजू को जवाब देने के लिए आगे किया था, उनका भाषण बहुत प्रभावी रहा।
- सूत्रों ने बताया, प्रियंका गांधी ने ही महिला सांसदों से, प्रधानमंत्री जहाँ बैठते हैं, उस जगह का घेराव करवाया और उनकी ही नीति थी कि कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में जाकर जवाब मांगें। इस प्रभावी रणनीति की वजह से ही पहली बार प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं बोल पाए, उन्हें मजबूरन राज्यसभा में जवाब देना पड़ा।
- सूत्रों ने कहा कि प्रियंका गांधी ही राहुल को भूपिंदर हुड्डा के लंच कार्यक्रम में ले गईं, जो वे हर वर्ष मीडिया व विभिन्न नेताओं के लिए आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में राहुल और प्रियंका आकर्षण का केन्द्र बने रहे।
- पर, इससे राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले उन नेताओं को अवश्य भारी ईर्ष्या हुई, जो अब तक संसद में पार्टी की गतिविधियों को मैनेज करते रहे हैं।

जवाब दिया, और ऐसे कई अन्य उदाहरण सामने आए

जहाँ राहुल गांधी सरकार पर लोकसभा में बोलने की अनुमति न

मिलने को लेकर लगातार हमला बोलते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम के मु.मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, शिक्षाविदों, डॉक्टरों, लेखकों और सेवानिवृत्त नौकरशाहों सहित, 40 से अधिक सूचित नागरिकों (इन्फोर्मड सिटीज़न्स) ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा एक विशेष समुदाय के खिलाफ दिए गए

- 40 से ज्यादा प्रबुद्धजनों, जिनमें डॉक्टर, शिक्षाविद्, लेखक व पूर्व नौकरशाह शामिल हैं, ने हिमन्ता बिस्वा सरमा के खिलाफ अपील की है और हेट स्पीच के लिए स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है।

हालिया बयानों पर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेने का आग्रह किया है।

उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि “संवैधानिक उल्लंघनों के खिलाफ चुप्पी या निष्क्रियता” से “स्वयं संविधान की नैतिक प्रामाणिकता क्षीण हो सकती है।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अशुतोष कुमार को लिखे पत्र में नागरिकों ने उच्च न्यायालय का ध्यान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश के हालात पर कब तक तटस्थ रहेगा भारत?

बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ निरंतर बढ़ती हिंसा को लेकर भारत में यह सवाल पूछा जा रहा है

- चुनाव नज़दीक आने के साथ हिंसा और तेज हो गई है। पर, भारत ने अपने बॉर्डर सील कर रखे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है।
- लेकिन मुद्दा यह है कि अगर ऐसे ही हिंसा बढ़ती रही तो भारत को अंततः बॉर्डर खोलना पड़ेगा, इससे भारत में भी नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

अपरिहार्य हो सकता है।

ऐसी स्थिति पूर्वी भारत के राज्यों पर भारी दबाव डाल सकती है। जैसे- जैसे बांग्लादेश की हालत दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है, भारत को, बढ़ते संकेत को रोकने के लिए मामले को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

देश कुलमिलाकर अनिश्चितता का सामना कर रहा है और प्रधानमंत्री श्रेष्ठ हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद, सत्ता संभालने वाली अंतरिम सरकार शासन की ठीक व्यवस्था देने में बुरी तरह असफल रही है।

आज, शुक्रवार 6 फरवरी को, बांग्लादेश में सरकारी कर्मचारियों ने वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन की मांग को लेकर बड़ा

प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस, साइंड ग्रेनेड और अन्य डराने वाले तरीकों का इस्तेमाल किया गया।

तथापि, गुस्साएं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और अंतरिम सरकार के प्रमुख, मोहम्मद यूनूस के आवास के पास पहुंच गए। जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, तो पुलिस ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी।

इस बीच, बांग्लादेश में 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं और इस्लामी संगठन किसी भी तरह सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी जमात पार्टी ज्यादा समर्थन पाने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रैपिड रेल के लिए देश भर में भारी रूझान

दिल्ली के बाद केरल में भी रैपिड रेल योजना को मंजूरी दी गई

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। भले ही नई दिल्ली और मेरठ के बीच 82 किमी दूरी को जोड़ने वाली भारत की पहली रैपिड रेल का औपचारिक उद्घाटन होना अभी बाकी है, लेकिन यह अवधारणा राजनीतिक नेताओं और नीति-निर्माताओं का आकर्षण पैदा कर चुकी है। 29 जनवरी को मेट्रो और शहरी रेल परिवहन की नोडल एजेंसी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने पहले चरण में 93 किमी लंबे दिल्ली-बावल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 32,000 करोड़ रुपये है और इसमें 22 स्टेशन होंगे, जो मानेसर और बावल जैसे औद्योगिक केंद्रों को सेवा देंगे।

दूसरे चरण में बावल से बहरोड़ तक लाइन का विस्तार किया जाएगा। हरियाणा सरकार पहले ही दिल्ली-शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ और

- केरल सरकार ने तिरुवनन्तपुरम और कासरगोड के बीच 583 किलोमीटर लम्बे रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी, जिसमें मौजूदा मेट्रो सिस्टम को भी जोड़ा जाएगा।
- दिल्ली में अभी नई दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले रैपिड रेल कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन होना बाकी है। पर, शहरी आवास एवं नगर विकास मंत्रालय ने दिल्ली-बावल के बीच 93 किलोमीटर के रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है।
- संसद में प्रस्तुत इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में 2900 किलोमीटर लम्बे रेल मार्ग पर रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

दिल्ली-पानीपत परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है।

वामपंथी शासित केरल सरकार ने भी तिरुवनंतपुरम से कासरगोड को जोड़ने वाले 583 किमी लंबे

आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण की योजना को स्वीकृति दी है, जिसमें भारत को मौजूदा मेट्रो प्रणालियों के साथ एकीकरण की योजना है और चरणबद्ध (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2025 के बिहार

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव हारने के बाद आप चुनाव को रद्द करवाना चाहते हैं, जब यह योजना चल रही थी, तब हमारे पास कोई नहीं आया, और वैसे भी आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए।

विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक राज्य कल्याण योजना का दुरुपयोग किया गया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 6 फरवरी। भारत की ओर से पेरिस पैरालंपिक गेम्स-2024 तथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भाग लेकर मैंडल जीत चुके निहाल सिंह को राजस्थान सरकार ने ढाई साल बाद भी “असिस्टेंट एक्साइज़ ऑफिसर” के पद पर नियुक्ति नहीं दी है। जबकि खेल एवं युवा मामलात मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के लिए 29 सितंबर 2023 को ही आदेश जारी कर दिए थे। परंतु ढाई साल बाद भी राज्य सरकार के वित्त, आबकारी और अन्य संबंधित विभागों द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। ऐसे में अब निहाल सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस प्रकरण में न्यायाधीश समीर जैन ने सुनवाई के बाद मामले की अगली तारीख 9 फरवरी तय की है। उन्होंने इस

- हैरानी की बात यह है कि आबकारी विभाग ने पद नहीं होने का हवाला देकर निहाल सिंह को नौकरी देने से मना कर दिया।
- पिछले ढाई साल में सरकार और कोर्ट में लगातार चक्कर काटने के बावजूद पीड़ित को न्याय नहीं मिला, जबकि, हाई कोर्ट में भी कई बार सुनवाई हो चुकी है।

- निहाल सिंह का कहना है कि, राजस्थान सरकार ने पैरालंपिक खिलाड़ी, अवनी लेखरा, सुंदर गुर्जर और देवेन्द्र झांझड़िया को तो “असिस्टेंट कन्जर्वेटर फॉरेस्ट” के पद पर नियुक्तियां दे दीं, परंतु मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है।”

मामले को पूरक सूची (सप्लीमेंट्री लिस्ट) में सूचीबद्ध किया है, ताकि मामले की सुनवाई अवश्य हो। इस मामले में याचिकाकर्ता की

ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद पैरवी के लिए पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि निहाल सिंह, भारत की पैरालंपिक टीम के सदस्य हैं। उनकी

टीम ने 20 से ज्यादा पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। वे खुद भी पेरिस पैरालंपिक गेम्स-2024 तथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भाग लेकर मैंडल जीत चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि पर राजस्थान सरकार ने उन्हें “ए-श्रेणी” के खिलाड़ियों में दर्ज किया था। साथ ही गत 29 सितंबर 2023 को “असिस्टेंट एक्साइज़ ऑफिसर” के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की थी। परंतु 4 दिसंबर 2023 को ही अतिरिक्त आबकारी आयुक्त ने पद नहीं होने का हवाला देकर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब मामला विशेष योग्यजन आयुक्त के पास पहुंचा तो उन्होंने 12 नवंबर 2024 को आबकारी कमिश्नर को पत्र लिखकर इस संबंध में नियुक्ति की कार्रवाई करने के लिए कहा। परंतु (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ में बदलाव अचानक नहीं हुआ

यह लम्बी चली बैंक चैनल वार्ताओं, अहम् के टकराव, रणनीतिक तालमेल की कहानी है

- बाज़ार जिसे बड़ी सफलता बता रहे हैं, वह असल में खुले टकराव के बाद आई कूटनीतिक शांति का नतीजा है।
- भारत व अमेरिका के बीच पिछले साल भारी तनाव उत्पन्न हो गया था, जब डॉनल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ लगाया था। उन्होंने भारत पर, बाज़ार, खासकर कृषि एवं डेयरी सेंक्टर, नहीं खोलने व रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड देने का आरोप लगाया।
- पर, भारत ने इसके लिए टकराव के बजाय बातचीत से समाधान का रास्ता चुना, साथ ही यह संकेत भी दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। धीरे-धीरे भारत के रणनीतिक प्रयासों का असर दिखने लगा और ट्रंप का रूख नरम पड़ा और अंततोगत्वा उन्होंने 18 प्रतिशत टैरिफ के साथ ट्रेड डील घोषित कर दी।
- लेकिन ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि टैरिफ में बदलाव भारत की मंज़िल नहीं है, यह मंज़िल के रास्ते का एक पड़ाव अवश्य है, अभी एक लंबा रास्ता तय करना है।

बाद हुई नेता स्तर की कई बातचीत ने संबंध सुधार के संकेत दिए। इसका

औपचारिक नतीजा इस सप्ताह सामने आया। भारतीय निर्यात के ज्यादातर

सामानों पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया, रूसी तेल

जयपुर, 6 फरवरी। पटवारी भर्ती परीक्षा-2021 में फर्जीवाड़े के सम्बंध में एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। एसओजी ने धोखाधड़ी कर पटवारी बने

- वर्ष 2021 में डमी से परीक्षा दिलाकर गीतेश जादौन का फर्जी तरीके से चयन हो गया और वह सरकारी सेवा में कार्यरत भी हो गया।

मूल अभ्यर्थी और उसके स्थान पर परीक्षा देने वाले डमी कैडिडेट (फर्जी अभ्यर्थी), दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि वर्ष 2021 की पटवार भर्ती परीक्षा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट जज ने जिंदा बम प्रकरण की सुनवाई से खुद को अलग किया

जयपुर, 6 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के एक जज ने शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बीच जिंदा मिले बम को लेकर मिली आजीवन कारावास की सजा को खिलाफ अपील पर सुनवाई से स्वयं को

- जस्टिस शर्मा सीरियल बम ब्लास्ट पर खंडपीठ का हिस्सा रह चुके हैं।

अलग कर लिया। ऐसे में एक्टिंग सीजे

अन्य खंडपीठ का गठन करेंगे। दरअसल, सरवर आजमी और शाहबाज हुसैन की अपील पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ के जज समीर शर्मा ने स्वयं को अलग कर लिया। जस्टिस समीर जैन उन खंडपीठ का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने पूर्व में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आरोपियों को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया था।

1.18 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। राजधानी में मादक पदार्थ तस्करो के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) और सांगानेर थाना पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर कल्याण सिंह (22) निवासी जिला राजगढ को गिरफ्तार

कर उसके कब्जे से करीब 589.95 ग्राम स्मैक बरामद की है। पकड़ी गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपये आंकी जा रही है। फिलहाल आरोपी तस्कर से पूछताछ की जा रही है।

कैप्चा सॉल्विंग के नाम पर ठगों का नया जाल

जयपुर । घर बैठे आसान कमाई का सपना देखने वालों के लिए एक खतरनाक जाल बिछाया जा रहा है। महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम के निदेशन में साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने एक ऐसे ट्रेंड का खुलासा किया है, जो कैप्चा सॉल्विंग के नाम पर मासूम लोगों की मेहनत की कमाई डकार रहा है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि ठगों की कार्यप्रणाली बेहद शातिर है। ये जालसाज फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर लुभावने विज्ञापन चलाते हैं। विज्ञापन में दावा किया जाता है कि आपको केवल स्क्रीन पर दिखने वाले कैप्चा कोड टाइप करने हैं और बदले में आप हर महीने हजारों रुपये कमा सकते हैं। न्यूनतम प्रयास और अधिकतम लाभ का लालच बेरोजगार युवाओं और गृहणियों को आसानी से अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इनके झांसे में आता है, उसे एक फर्जी जॉब एप्लीमेंट दिखाया जाता है ताकि सब कुछ असली लगे। इसके बाद शुरू होता है वसूली का खेला। कभी सॉफ्टवेयर चार्ज, कभी ट्रेनिंग फीस तो कभी सिक्वोरिटी डिपॉजिट के नाम पर पीड़ित से हजारों रुपये जमा करवा लिए।

बिना आयोडिन का 92 हजार किलो नमक जब्त

जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर के निदेशन में प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुद्ध आहार-मिलावट पर आहार अभियान के तहत शुक्रवार को 92 हजार किलो से अधिक नमक जब्त किया गया, जिसमें आयोडीन नहीं था। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि शुद्ध आहार-मिलावट पर अभियान के तहत शुक्रवार को अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नावा सिटी स्थित

नमक फैक्ट्री मैसर्स कस्तूरी कैमफूड प्रा.लि. पर कार्रवाई की गई। यहाँ पर टीटू ब्रांड नाम से लगभग 92 हजार 500 किलो नमक मौके पर पाया गया, जिसकी आयोडिन स्पट टेस्ट कटि से जाँच करने पर पाया गया कि नमक में आयोडिन की मात्रा नहीं थी। फर्म मालिक राहुल काला ने भी नमक में आयोडिन नहीं होना स्वीकार किया। मौके से नमक का सैंपल एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया। लगभग 92 हजार 500 किलो नमक मौके पर सीज किया गया। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो डालने वाला युवक गिरफ्तार

जयपुर । सोशल मीडिया पर रसूख दिखाने के लिए अवैध हथियारों के साथ फोटो अपलोड करने वाले युवाओं के खिलाफ जयपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन आग के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध देशी कट्टा बरामद किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त (जयपुर पश्चिम) हनुमान प्रसाद ने बताया कि शहर में अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस की साइबर टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों की निगरानी कर रही थी। जिन्होंने हथियारों के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी। निगरानी के दौरान एक युवक का फोटो देशी कट्टे के साथ मिला। जिसे पुलिस ने तुरंत चिन्हित किया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार गुप्ता और एसीपी (झोटाबाड़ा) आलोक सैनी के सुपरविजन में थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मुखबि की सूचना पर पुलिस ने रोड नंबर 9 स्थित सेंट्रल कॉलोनी में राजे डेव मॉंदर के सामने घेराबंदी की। वहां मौजूद संदिग्ध शक्ति कुमार उर्फ गड्डू (22) की तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा हथियार



का लाइसेंस मांगने पर वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। गिरफ्तार आरोपी राजकुमार उर्फ गुड्डू मूलतः अनाह गेट (भरतपुर) का रहने वाला है और वर्तमान में मुरलीपुरा के सीकर रोड स्थित रोड नंबर 8 पर किराए से रह रहा था। अब पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी यह हथियार कहाँ से लेकर आया था और उसका उद्देश्य क्या था। इस सफल कार्रवाई में थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील के साथ हेड कॉन्स्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल लोकेश, कान सिंह और महेश की विशेष भूमिका रही।

साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बताए गए उपायों के लिए क्या किया?

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस प्रकरण में जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अदालत की ओर से पूर्व में बताए उपायों के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। वहीं शेष काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश साइबर अपराध से जुड़े मामले में दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में एसीएस गृह भास्कर ए. सावंत, डीजी अग्रवाल, संचय संचय अग्रवाल, एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह सहित विधि सचिव अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने कहा कि वे मामले में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर को बुलाने के बाद भी अब तक ऐसे मामलों में कुछ नहीं किया गया। अदालती आदेश के बावजूद साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर नहीं बना है। इस पर एसीएस भास्कर सावंत ने कहा कि इसके लिए करीब दस हजार वर्गफीट जगह चाहिए। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है। उन्होंने भी सेंटर बनने का आश्वासन दिया है। इस पर अदालत ने कहा कि कोई समस्या हो तो बताओ, हम न्यायिक आदेश जारी कर देते हैं। आप बिड़िंगा चिन्हित करो, आदेश हम कर देते हैं। वहीं एफएसएल विंग में कर्मचारियों

की कमी को लेकर वीके सिंह ने कहा कि आरपीएससी की परीक्षा में योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। इस पर अदालत ने कहा कि सालों से जो संविदा पर काम कर रहे हैं, उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। जिला मुख्यालय पर साइबर अपराध विशेषज्ञ सरकारी वकील की नियुक्ति पर एसीएस ने कहा कि हर जिला मुख्यालय पर एक और हाईकोर्ट की दोनों पीठ में एक-एक विशेषज्ञ सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। पन्द्रह दिन में सभी नियुक्तियां हो जाएंगी। अदालती की ओर से डिजिटल उपकरणों की खरीद के मामले में जानकारी देते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अधिकतर केस सिम काई और बैंक खातों से जुड़े हैं, लोग अपने सिम काई और बैंक खाते इन्हें बेच देते हैं। इन्हें चिन्हित कर ब्लॉक करने का काम भी चल रहा है। अदालत ने चिंता जताई की गीग वर्कर्स के रूप में घरों में कौन घुस रहा है, किसी को पता नहीं है। पंजीकृत एक व्यक्ति है, लेकिन आता दूसरा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने हल्के अंदाज में कहा कि आज भी हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन हमेशा कोर्ट को ही यह धमकी क्यों मिल रही है। आज तक पुलिस के भवन में बम धमाका करने की ई-मेल किसी ने नहीं भेजी।

विदेशी एमबीबीएस डॉक्टरों को फर्जी सर्टिफिकेट बेचने वाला सरगना एसओजी के हथ्थे चढ़ा

थाईलैंड और दुबई में छिपा था मुख्य आरोपी, कजाकिस्तान से लौटा डॉक्टर बना दलाल

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आने वाले अभ्यर्थियों को फर्जी स्क्रीनिंग टेस्ट पास सर्टिफिकेट मुहैया कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसओजी ने गिरोह के मुख्य सरगना सहित एक अन्य डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह उन डॉक्टरों को निशाना बनाता था जो भारत में प्रैक्टिस के लिए जरूरी विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) परीक्षा पास नहीं कर पाते थे।

जलदायकर्मों 9 फरवरी को करेंगे प्रदर्शन

जयपुर। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन (इटक) जयपुर के आह्वान पर 9 फरवरी को सैकड़ों कर्मचारी अपनी लॉबि तमांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पानी पेच जयपुर पर विरोध-प्रदर्शन करेंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत एवं जिला अध्यक्ष ताराचन्द सैनी ने संयुक्त रूप से बताया कि विभाग द्वारा लंबे समय से जलदाय कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इसी के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर जलदाय कर्मचारियों की आम सभा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों को मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी तथा आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आने वाले अभ्यर्थियों को फर्जी स्क्रीनिंग टेस्ट पास सर्टिफिकेट मुहैया कराने वाले मुख्य आरोपी भानाराम माली उर्फ भानू (30) निवासी ब्यावर पिछले काफी समय से फरार था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई, कजाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में ठिकाने बदल रहा था। एसओजी की टीम को सूचना मिली कि वह दिल्ली पहुंचने वाला है। जिस पर टीम ने जाल

■ **विदेश से डिग्री लेकर आए 73 अन्य डॉक्टरों की भूमिका भी जांच रही एस.ओ.जी.**

बिछाकर उस एयरपोर्ट से दस्तयाब कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फिलहाल सात फरवरी तक पुलिस रिमांड पर है।

जांच में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया है। एसओजी ने डॉ. इन्द्रराज सिंह गुर्जर (27) निवासी

करौली को भी गिरफ्तार किया है। इन्द्रराज खुद कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर लौटा था, परंतु परीक्षा पास नहीं कर सका। उसने आरोपी भानाराम को पैसे देकर दिसंबर 2022 का कूटरचित एफएमजीई सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इसी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उसने अलवर के राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज से इंटरनशिप पूरी की और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी हासिल कर लिया। बाद में वह अन्य अभ्यर्थियों को भी फर्जी सर्टिफिकेट दिलवाने के खेल में शामिल हो गया। एसओजी की जांच में यह तथ्य

वास्तुकार प्रमोद जैन को 1 2वाँ ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवॉर्ड

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रसिद्ध वास्तुकार प्रमोद जैन को उनके उत्कृष्ट प्रोजेक्ट मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के लिए प्रतिष्ठित 12वाँ ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवॉर्ड (आइसा)- 2025 प्रदान किया। वास्तुकार प्रमोद जैन को बतौर पुरस्कार ट्रॉफी और 1 लाख की नकद राशि प्रदान की गई। उन्हें यह सम्मान जेईसीसी सीतापुर में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट में शुक्रवार शाम को दिया गया।

पुरस्कार प्रशस्ति पत्र में वास्तुकार जैन को एक दूरदर्शी वास्तुकार बताते हुए पथर के अभिनव और उत्कृष्ट उपयोग के लिए उनकी सराहना की गई। जूरी ने विशेष रूप से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर को जोधपुर की समृद्ध स्थापत्य विरासत से प्रेरित एक उत्कृष्ट भवन बताया। स्थानीय सूरसागर सैंडस्टोन से निर्मित यह भवन पारंपरिक पथर निर्माण तकनीकों को समकालीन और नवाचारी शैली में प्रस्तुत करता है। इसकी आकर्षक मुखाकृति, भव्य प्रवेश द्वार और सूक्ष्म पारंपरिक अलंकरणों की विशेष प्रशंसा की गई। इस पुरस्कार चयन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया, जिसमें कार्डिसल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए), नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स



(आईआईए), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स (आई आईआईडी), मुंबई के अध्यक्ष तथा इंडियन सोसाइटी ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स (आइसोला) के अध्यक्ष शामिल थे।इससे पूर्व भी वास्तुकार प्रमोद जैन को लगातार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) जयपुर के लिए डिजाइन स्केप अवॉर्ड- 2024 तथा एमआईसी, जोधपुर के लिए वर्ष 2025 में मिल चुका है।

पीएम कुसुम योजना में प्रदेश ने 3 हजार मेगावाट क्षमता अर्जित की

राजस्थान अक्षय एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहले पीएम कुसुम योजना (कम्पोनेन्ट ए तथा सी) में राजस्थान ने तीन हजार मेगावाट की क्षमता अर्जित की है। डबल इंजन सरकार के विजन से किसान 'अन्नदाता' के साथ 'ऊर्जादाता' और प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बन रहा है। मुख्यमंत्री ने पीएम कुसुम योजना की इस उपलब्धि के लिए मेहनती किसानों, ऊर्जा विभाग

और राजस्थान डिस्कॉम्स के कार्मिकों को बधाई दी है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के साथ-साथ पीएम कुसुम योजना कम्पोनेन्ट ए तथा सी में देश का अग्रणी राज्य है। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को अब दिन में बिजली मिल रही है। साथ ही, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम्पोनेन्ट बी में सोलर पम्पसेट लगाने पर अनुदान

भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट-सी के अन्तर्गत विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर चुके प्रदेश के ऊर्जादाताओं तथा डवलपरो के लिए केन्द्रीय सहायता स्वीकृत हुई है। केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रथम चरण में 46 करोड़ 64 लाख रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता जारी करने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बताए गए उपायों के लिए क्या किया?

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस प्रकरण में जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अदालत की ओर से पूर्व में बताए उपायों के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। वहीं शेष काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश साइबर अपराध से जुड़े मामले में दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में एसीएस गृह भास्कर ए. सावंत, डीजी अग्रवाल, संचय संचय अग्रवाल, एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह सहित विधि सचिव अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने कहा कि वे मामले में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर को बुलाने के बाद भी अब तक ऐसे मामलों में कुछ नहीं किया गया। अदालती आदेश के बावजूद साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर नहीं बना है। इस पर एसीएस भास्कर सावंत ने कहा कि इसके लिए करीब दस हजार वर्गफीट जगह चाहिए। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है। उन्होंने भी सेंटर बनने का आश्वासन दिया है। इस पर अदालत ने कहा कि कोई समस्या हो तो बताओ, हम न्यायिक आदेश जारी कर देते हैं। आप बिड़िंगा चिन्हित करो, आदेश हम कर देते हैं। वहीं एफएसएल विंग में कर्मचारियों

की कमी को लेकर वीके सिंह ने कहा कि आरपीएससी की परीक्षा में योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। इस पर अदालत ने कहा कि सालों से जो संविदा पर काम कर रहे हैं, उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। जिला मुख्यालय पर साइबर अपराध विशेषज्ञ सरकारी वकील की नियुक्ति पर एसीएस ने कहा कि हर जिला मुख्यालय पर एक और हाईकोर्ट की दोनों पीठ में एक-एक विशेषज्ञ सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। पन्द्रह दिन में सभी नियुक्तियां हो जाएंगी। अदालती की ओर से डिजिटल उपकरणों की खरीद के मामले में जानकारी देते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अधिकतर केस सिम काई और बैंक खातों से जुड़े हैं, लोग अपने सिम काई और बैंक खाते इन्हें बेच देते हैं। इन्हें चिन्हित कर ब्लॉक करने का काम भी चल रहा है। अदालत ने चिंता जताई की गीग वर्कर्स के रूप में घरों में कौन घुस रहा है, किसी को पता नहीं है। पंजीकृत एक व्यक्ति है, लेकिन आता दूसरा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने हल्के अंदाज में कहा कि आज भी हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन हमेशा कोर्ट को ही यह धमकी क्यों मिल रही है। आज तक पुलिस के भवन में बम धमाका करने की ई-मेल किसी ने नहीं भेजी।

रीको के 2 4 नए औद्योगिक क्षेत्रों में मिलेगा पेयजल

जयपुर । रीको द्वारा प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रीको के 24 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगभग 143 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था पीएचईडी के माध्यम से कराई जाऐगी।

रीको के नवीन औद्योगिक क्षेत्र

■ **इस प्रोजेक्ट पर करीब 143 करोड़ रुपए खर्च होंगे**

बडागंवा (सिरोही), मसुदा, किशनगढ़- 6 एवं खोडा (अजमेर), रामा आसपुर (डूंगरपुर), प्रतापगढ़ एक्सप्रेशन (प्रतापगढ़), कोटड़ा (धौलपुर), करनपुरा, उखालिया, फतेहपुरा समेलिया (भीलवाड़ा), मलसीसर

(झुन्झुं), खुडियाला एवं तिवरी (जोधपुर), सियामाली एवं बडी सीड (फलीदी), हरसीर (नागौर), श्रीराम जानकी राजास (डोंडवाना-कुचामन), डोला जागीर, नाडोल एवं वरकाना (पाली), स्टोन पार्क मासलपुर (करौली), श्रीराम जानकी जटलाव गोठडा (सवाई माधोपुर), मऊ एवं नीमकाथाना-द्वितीय (सीकर) में कार्यरत इकाइयों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा । रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी

स्वर्णकार ने बताया कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों व कामगारों को आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध की जा रही है। रीको का हरसंभव प्रयास रहा है कि निवेशकों को रीको औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने एवं उनके संचालन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो ताकि वे निर्बाध रूप से अपने उद्योगों को संचालन कर सकें। इसी उद्देश्य से रीको प्रदेश में औद्योगिक ढांचे के सर्वांगीण विकास में जुटा है।

दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स का सम्मान

जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राष्ट्रीय कैडेट कोर को विद्यार्थी जीवन को गढ़ने वाला बताते हुए कहा कि यह देश का अनुशासित, राष्ट्र प्रतिकर्षक सैन्य प्रशिक्षण से ही जुड़ा संगठन नहीं है बल्कि आपदा काल में देश सेवा से जुड़ा भी प्रमुख संगठन है। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान कैडेट्स के परेड में भाग लेने और सांस्कृतिक आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की।

राजस्थानाल बागडे शुक्रवार को लोकभवन में दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स के सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं के चरित्र निर्माण के साथ-साथ सेवा और एकता की भावना जगाने वाला संगठन है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स एक बार इसमें आता है तो फिर हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाता है। उन्होंने सभी को देश को समृद्ध बनाने में भूमिका निभाने का आह्वान किया।

उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने एनसीसी को चरित्र निर्माण की



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित समारोह में एनसीसी कैडेट्स का सम्मानित किया।

पाठशाला बताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस संगठन के विकास के लिए निरंतर प्रशिक्षण है। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करने का आह्वान किया। इससे पहले राज्यपाल बागडे ने

एनसीसी के विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कैडेट्स सीनियर अंडर ऑफिसर मोनिका, सलीनी यादव, नमन चौधरी, आयुषी जैन और अंडर ऑफिसर युवराज राठौड़ को लोकभवन में सम्मानित किया। उन्होंने चयनित

■ **राष्ट्रीय कैडेट कोर विद्यार्थी जीवन को गढ़ने वाला : बागडे**

■ **समारोह में कैडेट्स ने लोक संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां दी**

कैडेट्स को उपहार भी प्रदान किए। कर्नल नितिन ने गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान के एनसीसी कैडेट्स के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका और राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी भी उपस्थित रहे। छात्र-छात्राओं ने इस अवसर पर राजस्थान की लोक संस्कृति और परम्पराओं से जुड़ी नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां दीं। बिड़ला बालिका विद्यापीठ, पिलानी की छात्राओं ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रस्तुत राष्ट्र भक्ति से जुड़ी मधुर धुनें बैठ पर पेश कीं।

32वां ध्रुवपद समारोह 10 को

जयपुर (कासं)। इंटरनेशनल ध्रुवपद धाम ट्रस्ट एवं रसमंजरी संगीतोपासना केन्द्र, उदयपुर की सहभागिता में राजस्थान की ध्रुवपद - विरासत के हस्ताक्षर ध्रुवपदाचार्य पंचश्री पं लक्ष्मण भट्ट तैलंग की पुण्यतिथि 10 फरवरी को 32वां अखिल भारतीय ध्रुवपद नाद-निनाद विरासत समारोह जयपुर ध्रुवपद धरोहर आयोजित किया जाएगा। जवाहर कला केन्द्र के कृष्णयान सभागार में सयंय 6 बजे से विभिन्न प्रस्तुतियां होंगी। इसका प्रारम्भ भारत के 150 वर्ष पूर्ण कर चुके राष्ट्रीत वन्देमारम् के गौरव-गान से होगा, उसकी गुण-वखान की विविधता के भाव के अनुरूप परम्परागत धुन को नवीन ध्रुवपद के छंद में कुछ नये स्वर – संयोजनों के सौन्दर्य के साथ विस्तार दिया जायेगा, जिसे ध्रुवपद - गाथिका प्रो. मधु भट्ट तैलंग के निदेशन में उनके शिष्य प्रस्तुत करेंगे।

सार-समाचार

डॉ. लीलाधर के काव्य संग्रह का विमोचन



जयपुर । सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सेवानिवृत्त उप निदेशक डॉ. लीलाधर दोचानिया के नव प्रकाशित कविता संग्रह “जिन्दगी मुस्कुराती रहे...” का विमोचन शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में संभ्र हुआ। विमोचन वरिष्ठ साहित्यकार और फिल्म लेखक त्रिलोक चंद कौशिक, महाराष्ट्र के वरिष्ठ साहित्यकार मनोभा खटाते ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि डॉ. लीलाधर अपनी कविताओं के जरिये एक मुस्कुराते हुए समाज का स्वप्न देखते है और उन चीजों की गहरी पड़ताल करते है जो हमें निरंतर अमानुष बना रही है। कविताएं नकारात्मक माहौल में सकारात्मक सन्देश देती है। जीवन की सहज अनुभूतियों और संवेदनाओं को प्रकट करता कविता संग्रह समाज और जीवन की विमर्शतियों और सच्चाइयों को रेखांकित करती है। कवि की गहन सोच शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है। ऐसा लगता है कविताएं उनके मन की अकुलाहट और चिंतन का साक्षात परिणाम है। समारोह में लीलाधर ने भी अपनी कुछ रचनाओं का वाचन किया। समारोह का संयोजन सीमा वालिया ने किया । इस अवसर पर वरिष्ठ रंगकर्मी, नाटककार और जाने माने कलाकार ईश्वर दत्त माथुर, वरिष्ठ लेखक और पत्रकार बाल मुकुंद ओझा, वरिष्ठ साहित्यकार नन्द भास्कराज, वरिष्ठ जनसम्पर्ककर्मी और कवि गोविन्द शर्मा, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी कनिष्क सैनी, कमांडेंट सतवीर सिंह, दलीप सिंह सहित अनेक प्रमुख लोग उपस्थित थे।

न्यू लोहा मंडी तक हटाए अतिक्रमण



जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने सीकर रोड पर 200 फीट बाईपास से न्यू लोहामंडी क्षेत्र तकवेब 2 किलोमीटर दूरी में अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई 100 फीट सड़क पर सुगम यातायात मुहैया करवाने के उद्देश्य से की गई। इसके अलावा करीब 5 बीघा निजी खालेदारी की जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया। इसी प्रकार सड़क मोड़ से मुख्य दिल्ली रोड आमेर, कुण्डा चैक पोस्ट तक भी अतिक्रमण हटाए गए। जे.एल.एन. मार्ग पर बिरला मंदिर से रामनिवास बाग तक दोनों तरफ सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया। महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया सीकर रोड पर 100 फीट सड़क सीमा में अवैध अतिक्रमणों के कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही थी। इसके लिए शुक्रवार को 200 फीट बाईपास से न्यू लोहा मण्डी तक 100 फीट सड़क सीमा में आ रहे चबूतरें, सीढ़ियां, लोहे के गेट, बाउण्ड्रीवाल, लोहे के ऐंगल, टीनशेड, रेलिंग, थंडियां, टेले, बांस-तम्बू, तिरपाल, काउण्टर, टेबल कुर्सियां, होट्टेई और साईन बोर्ड हटाए गए। इसके अलावा बस्सी के ग्राम भवासई ईशरवाला में 5 बीघा निजी खालेदारी की कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन और बिना भू रूपान्तरण करवाए काटी जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। यहां पर अवैध कॉलोनी के लिए भूमि समतल करके मिट्टी-प्रेवल की सड़कें, बाउण्ड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माण कर लिए गए थे।

महेन्द्र सिंह बने कार्यवाहक प्रांतीय अध्यक्ष

जयपुर । जल भवन में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का विशाल प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन ने प्रदेश की कर्मचारी राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया, जहाँ श्रीगंगागर से जैसलमेर और धौलपुर से बाड़मेर तक, राजस्थान के प्रत्येक जिले से आए हजारों कर्मचारियों के सीलाब ने संगठन की अटूट एकता का प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रवक्ता बलराम गुर्जर ने बताया कि अधिवेशन के दौरान लोकरतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए, प्रांतीय अध्यक्ष राजेश पारीक ने संघ के संविधान की धारा 12 (घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह की गुंजती तालियों और नारों के बीच महेन्द्र सिंह धायल (वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग) को कार्यवाहक प्रांतीय अध्यक्ष मनोनीत करने की घोषणा की। राजेश पारीक ने प्रदेश की समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी को तत्काल भंग करने का आदेश जारी किया।

भ्रामक विज्ञापन पर सलमान खान को राहत

जयपुर (कासं)। राज्य उपभोक्ता आयोग ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को राहत दी है। इसके साथ ही आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय को कहा है कि अवमानना करने वाले व्यक्ति पर यदि जमानती वारंट की तामील नहीं हो तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किए जाए। आयोग पुनः जमानती वारंट जारी कर सकता है, लेकिन गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाए। आयोग अध्यक्ष देवेन्द्र कच्छावा और सदस्य सुरेंद्र सिंह व करुणा जैन ने यह आदेश राजश्री पान मसाला की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

सीवर लाइन की मांग

जयपुर । पत्रकार कॉलोनी विकास समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस कॉ

